[Shri Jagjit Singh Anand]

atrocities on Harijans but also of the inadequacy of the election

1 P.M system in this country. It has not happened at one place and this power has not been exercised by one party but the parties in power. At least those sections which are more advanced and which are comparatively more assertive in the villages, those sections are still preventing the weaker sections and Harijans from exercising their votes. They told me that in their particular booth all the votes were cast and none of them was allowed to go in. In many parts of western U.P., it has been brought to my notice —by my own colleagues also- that large scale rigging had taken place. I condemn rigging whether it is in western U.P., whether it is in Andhra, Bihar or in any other State ruled by a one-man party or another. But I want to ask the hon. Home Minister through you, Sir, when will his party which has always been talking of protection to Harijans see that this thing comes to an end, when will such procedures be followed and such processes brought into play when there is a really fair election in this country when people who want to vote in a particular manner are free to vote in that particular manner and heads are not broken of poor people, old people, and children are not going to be allowed to die and then go unburied for days together and cattle are not going to starve to death? Thank you, Sir, for allowing me.

THE APPROPRITION BILL, 1980— *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We now resume further discussion on the motion for consideration of the Appropriation Bill. We won't have a lunch-break in view of the business before the House.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, जो विधेयक राज्य वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें आप देखेंगे कि पिछली सरकार ने बजट में जो प्रावधान किया था उसमें जो अधिक खर्च हुआ हैं, उसके लिए यह अनुपूरक मांग रखी गयी है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात पर हम चर्चा करें कि पिछली सरकार ने किन मदों पर यह अधिक खर्च किया जिसकी स्वीकृति संसद ने नहीं दी थी और क्या वे कार्य ऐसे हैं जो उन्हें करने चाहिये थे। जहां तक कि मांग के समर्थन का सवाल है उसमें कोई विवाद नहीं है। अब तो रुपया खर्च हो चुका है। सरकार का काम था, उसने अच्छा किया कि उस खर्चे की मंजूरी के लिए इस सदन के सामने यह विधेयक रखा। लेकिन मान्यवर, उसके साथ साथ मैं यह उचित समझता हूं कि सदन इस बात पर गौर करे कि पिछली सरकार ने किस प्रकार से इतने मूल्यवान धन का अपव्यय किया। उस सिलसिले में इस बात की सबसे अधिक चर्चा होनी चाहिए और जिसके एक अंश की चर्चा प्रातःकाल यहां हुई थी मैं उस तरफ़ आपके माध्यम से सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। पिछली जनता सरकार और लोक दल सरकार ने अगर देश के विकास के लिए, कुछ नया काम करने के लिए, शासन तंत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, मजदूरों की खुशहाली के लिए, उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए कोई कार्य किया होता तो अवश्य ही हम उनकी प्रशंसा करते। लेकिन अफसोस है कि जनता पार्टी ने अपने शासन काल में जिस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी वह कार्य था अपने विरोधियों के प्रति प्रतिशोधात्मक कार्यवाही को करना और उसे करके श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लोगों तथा उनकी पार्टी के लोगों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से काम

करना ताकि उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाये । इस बात का बार बार ऐलान उन्होंने किया भी और इस चुनाव में भी इन दलों के नेताओं ने कहा कि उन्होंने श्रीमती गांधी को समाप्त कर दिया है, उसको दफ़न कर दिया है इसलिए अब उनको वोट देने से क्या फ़ायदा । इस प्रकार की बातों को उन नेताओं ने कहा । इसी तरह के प्रयास भी मान्यवर, उन्होंने पिछले तीन सालों से 77 से इस चुनाव के बीच के समय में, जितना समय मिला, इस काम की तरफ़ अपना ध्यान दिया ।

मान्यवर, प्रधान मंत्री ने सदन में राष्ट्रपति के भाषण के संदर्भ में अपने विचारों को प्रकट करते हुए कुछ सुचनाएं हमको दी थीं । लेकिन मैं समझता हूं कि सदन को इस बात की आवश्यकता है कि पिछले तीन साल के अन्दर जनता और लोक दल की सरकारों ने जितने कमीशन बनाये, जितनी रिपोर्टें पुलिस में दर्ज कीं, जितनी सी० बी० आई० के द्वारा अथवा पुलिस के द्वारा जांचे कराई गयीं या दूसरे प्रकार से इन तमाम बातों को विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने रखी जावे । एक व्हाइट पेपर उस पर सरकार पब्लिश करे ताकि इस बात का पता चल सके कि जनता सरकार ने अपने शासन काल में किस प्रकार के निन्दनीय कार्य जनतंत्र विरोधी कार्य, विरोधियों को हटाने का कार्य किये । हटाने का कार्य किस प्रकार से किया, उस पर एक व्हाइट पेपर छपना चाहिये कि कितना व्यय किया है, क्योंकि बहुत सा व्यय तो सामने आया और बहुत सा ऐसा व्यय है जो कर्मचारियों द्वारा खर्च किया गया, उनकी तनख्वाह, यात्रा भत्ते पर खर्च किया गया, जो इन कमीशनों के द्वारा सामने नहीं आया

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार एक व्यापक श्वेत पत्र प्रकाशित करे जिसमें तमाम जिस तरह से इन्होंने कार्यवाही की, कितने कमीशन बिठाए, कितनी जांच पड़ताल की रिपोर्टें दर्ज कीं, वह सब आएं ताकि देश को पता चल सके कि किस प्रकार इन्होंने प्रयास किया था इन्दिरा गांधी को समाप्त करने के लिये ।

दूसरी बात इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने यही नहीं किया कि उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास किया, बल्कि उनके घर को भी खोदा जो बन रहा था । उसके बारे में भी किन अधिकारियों ने कार्यवाही की और जिस व्यक्ति ने आदेश दिये, मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । श्रीमन्, इन्होंने कालपात्र खोदा जो एक एतिहासिक दस्तावेज था । यह उनके लिये बहुत दुख का विषय हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों की कमेटी बनाई और उस कालपात्र को खुदवाया और पचासों हजार रुपये उस पर खर्च किये और उस को तोड़ा जो बहुत ही सतर्कतापूर्वक और सावधानी के साथ दस्तावेज रखा गया था जिसमें भारत का संक्षिप्त इतिहास, उसके स्वाधीनता संग्राम का वर्णन, और बहुत सी तत्कालीन वस्तुएं थीं । उन सब को खोदा, पर उसमें कोई भी चीज़ निकल नहीं सकी जिससे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के खिलाफ़ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ़ उपयोग कर सकते । उनका शर्म के साथ सिर झुक जाना चाहिये था । लेकिन बेशर्म लोगों का सिर नहीं झुका । इसके बारे में जिन लोगों ने आदेश दिये थे, वह भी प्रकाश में आना चाहिये ।

जनता पार्टी राज्य में अधिकारियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उनका अपराध केवल यही था कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान की

[श्री श्याम लाल यादव]
काल में सरकार में किन्हीं पदों पर नियुक्त थे। अभी दो दिन पहले सी०बी० आई० के एन० के० सिंह के मामले को लेकर इतने विचार इस सदन में सदस्यों ने रखे। कई बातें सामने आई। मान्यवर सभापति जी ने भी अपनी व्यवस्था दी।

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी रिजीम में किस प्रकार से पेट्रोलियम सैक्रेट्री वोहरा को उनके दरफ्तर से नाजायज तौर से गिरफ्तार किया गया। उसका पूरा पत्र प्रकाशित हुआ है जो कैबिनेट सचिव को लिखा था। उस पत्र के एक-एक वाक्य से प्रकट होता है कि किस प्रकार से सरकार ने और उसके अधिकारियों ने गलत कार्यवाही, अवैधानिक कार्यवाही की। डी० सेन को किस तरह तबाह किया गया, किशन चन्द को तो आत्म हत्या तक करनी पड़ी, भिंडर को किस तरह से बर्बाद किया गया, नारंग, खुराना और द्विवेदी को—जो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, अब समय आ गया है कि उन तमाम कार्यवाही का अंत होना चाहिये। उनके साथ जो अपमानजनक कार्यवाही हुई, मेरा सरकार से निवेदन है कि उन पर पुनः नये सिरे से विचार होना चाहिये और उन अधिकारियों के सम्मान की समुचित रक्षा होनी चाहिये।

इस सिलसिले में, श्रीमन मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने स्पेशल कोर्ट बनाई थीं। जिस उद्देश्य से स्पेशल कोर्टस बनाई थीं, वह साफ जाहिर हैं, उसमें कोई बात छिपी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि स्पेशल कोर्टस को समाप्त करने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये और जो भी कार्यवाही इसके अन्दर हुई है उस सब को रद्द करना चाहिये। वह देश के साधारण कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिये। जनता पार्टी ने जब नहीं किया तो उस स्पेशल कोर्टस की कार्यवाही को समाप्त करना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी और कई लोगों ने इस तरह का बयान दिया, अभी इलाहाबाद के एक बड़े नामी वकील श्री पी० सी० चतुर्वेदी ने भी बयान दिया है, हमारे अस्थाना साहब ने उस बयान को देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि न्याय के सम्मान और उसकी गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिये उस प्रकार के स्पेशल कोर्ट एक्ट को तत्काल समाप्त करना चाहिये और जो जनता पार्टी ने इस देश की न्यायापालिका, के सिर पर कलंक का टीका लगाया था उसे समाप्त करना चाहिये। इस प्रकार के तमाम मुकद्दमे जनता पार्टी ने जिन लोगों पर भी चलाए थे वे समाप्त कर देने चाहिएं और वापिस ले लेने चाहिएं। चाहे वे अदालत में किसी भी स्टेज में हों, चाहे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हों, हाई कोर्ट में हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हों, ऐसे मुकद्दमों को सरकार को तत्काल वापस लेकर अपनी न्यायप्रियता को स्थापित करना चाहिए।

मान्यवर, अभी वैद्यलिंगम रिपोर्ट की चर्चा हुई। उस सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग दूध के धोये बनते थे उनके बारे में यह स्पष्ट हो गया कि वे शीशे के मकानों में रहते है। जिन दो व्यक्तियों के बारे में कहा जाता था कि उन के जैसा सच्चरित्र और ईमानदार इस देश में न पैदा हुआ है ना होगा, उन दोनों लोगों के बारे में वद्यलिंगम कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है वह काफी स्पष्ट है। जो अखबारों में

छपा है अगर वह सही है तो उस से साफ जाहिर हो जाता है कि जो दूसरों पर पत्थर फेंक रहे थे, दूसरों को तबाह कर रहे थे वे खुद शीशे के घर में रहते हैं और कितने ईमानदार और सच्चरित्र हैं वह इस रिपोर्ट से देश को पता लग जायेगा। इस लिए इस पर विचार होना चाहिए।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि परसों इस सदन में भंडारी जी ने अपने भाषण में कई आंकड़े पेश किये इस बात के कि जनता राज्य में क्या उपलब्धियां हुई, किस तरह उत्पादन बढ़ा, किस तरह क्या हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने ये आंकड़े पेश कर के केवल सदन को गुमराह करने की या भ्रामित करने की कोशिश की। जिस प्रकार का ठोस आर्थिक आधार कांग्रेस सरकार ने 1977 में छोड़ा था और जो ठोस आर्थिक आधार देश को दिया था और जिस को ले कर जनता पार्टी तीन साल तक चलती रही मैं समझता हूं कि उस आधार को जनता पार्टी ने अपने कुशासन से समाप्त कर दिया। उन्होंने देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विषमता की ऐसी भयंकर परिस्थिति पैदा कर दी कि देश की जनता ने यह महसूस किया कि कोई शासन नाम की चीज देश में नहीं रह गयी है। इस तरह की स्थिति लाने का सब से बड़ा श्रेय जनता पार्टी को है। जिस प्रकार से जनता पार्टी के शासन में हरिजनों, पर गिरिजनों पर, अल्पसंख्यकों पर, कमजोर वर्गों पर ज्यादतियां हुई, जुल्म हुए वह कहानी कही नहीं जा सकती। जिस प्रकार से साम्प्रदायिक दंगे—अकेले जमशेदपुर में चालीस हजार आदमी प्रभाति हुए—उसे भुलाया नहीं जा सकता। उस के अलावा बेलची में, मराठवाड़ा में, विल्लुपुरम में, कानपुर, मुजफ्फरपुर में, अलीगढ़ और पन्तनगर आदि तमाम स्थानों में जिस तरह अल्पसंख्यकों और हरिजनों पर जुल्म हुए उससे ऐसा प्रकट होने लगा कि शासन के हर अंग में, हर गोशे में आर० एस० एस० के लोग घुसे हुए हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने वहां पर घुस कर उस का पूरा फायदा उठाया है और मैं सरकार से चाहूंगा कि इस बात की व्यापक तौर से गहराई से जांच होनी चाहिए कि कहां-कहां आर० एस० एस० के लोग शासन के अन्दर घुस गये हैं, उन को हटाना चाहिए, उन्हें निकाल फेंकना चाहिए ताकि असाम्प्रदायिक स्वरूप शासन का बनाया जा सके। नहीं तो इस बात का खतरा है कि आर०एस०एस० वाले जहां शासन में बैठे हैं वहां से इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और समाज में विद्वेष या दुर्भावना फैलायेंगे। इसलिए, मान्यवर, इस पर गौर करना चाहिए।

दूसरी बात, जो इस समय सूखा पड़ा उस में कोई राहत का कार्य इन्होंने नहीं किया। यही नहीं, किसानों को उन की उपज का मूल्य नहीं मिला। जनता पार्टी इस नारे के साथ शासन में आयी थी कि गेहूं का मूल्य 150 रुपया दिया जायगा, गन्ने का, कपास का, मूंगफली का उचित मूल्य दिया जायगा, लेकिन कहीं नहीं दिया। किसानों का गन्ना खेतों में सूख गया, जला दिया गया, निकाले नहीं गये क्योंकि उन की ढुलाई और रखरखाव का इन्तजाम नहीं था। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने किसानों की जो दुर्व्यवस्था की उस का यह परिणाम हुआ कि किसानों ने विवश हो कर इन को शासन से हटा दिया।

[श्री श्यामलाल यादव]

मान्यवर, दो-तीन बातें कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं । जनता पार्टी ने सोने की नीलामी की । उस सोने की नीलामी का उद्देश्य घोषित किया था कि मंहगाई कम होगी, सोने का दाम कम होगा, स्मगलिंग कम होगी । लेकिन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई । यह आश्चर्य की बात है, चमत्कार है कि 17 टन सोना नीलाम किया गया 23 करोड़ रुपए का, लेकिन उस के बावजूद सोने के दाम बढ़ गये । सोने के दाम इतने बढ़ गये कि हमारे यहां जो परम्परा है कि लड़की की शादी या बहन की शादी पर उस को सोने का मंगलसूत्र देते हैं अब किसी प्रकार जरा-सा सोने का जेवर भी नहीं दे सकते । इस मामले में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है । मुझे आशा है देश के सामने इस बात की सफाई हो पायेगी कि सोने का जो नीलाम किया गया वह क्यों किया गया और उसके पीछे उद्देश्य क्या था और उस से किस किस का लाभ हुआ और उस में कितना घपला हुआ । यह देश के सामने पूरी तरह से आ सकेगा ऐसी मैं आशा करता हूं । इस के अलावा देश में औद्योगिक क्षेत्र में सब से बड़ी बाधा आयी और सरकार ने मोनोपोली हाउसेज को बढ़ाने की कोशिश की और देश में विकास की दर उन के कारण घटी ही नहीं, वरन माइनस 4 प्रतिशत हो गयी और ऐसा लगता है कि उन के इस तीन साल के शासन के परिणामस्वरूप यह विकास की दर बराबर गिरती ही चली जायेगी । कहां तो छठी योजना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि उस में होनी चाहिए थी, कहां उन के शासन के फलस्वरूप उस में 4 प्रतिशत की कमी आ गयी । यही इस बात का प्रमाण है कि जनता शासन में किस प्रकार से देश के अर्थ-तंत्र को और यहां की अर्थ-व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और उस का सब से बड़ा उदारण है कि देश में डिजल की भयंकर कमी हो गयी और इस के परिणामस्वरूप देश के किसानों को और देश के ट्रांस्पोर्टरों को आज डिजल नहीं मिल रहा है और उसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है । यह उन के कुशासन का और खराब नीतियों का परिणाम है । मैं चाहता हूं कि डिजल की कमी के कारणों को देखा जाय और देश में ऐसा वातावरण पैदा किया जाय कि जिस में यह कमी न रहे । आसाम में जहां तेल की रिफाइनरीज है वहां से ज्यादा से ज्यादा डिजल देश भर में उपलब्ध कराया जाय । इस की कमी के कारण देश में बड़ा भारी संकट है और इस के कारण देश की शासन व्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ता है ।

आखिरी बात कहना चाहता हूं कि अभी कलराज मिश्र जी कह रहे थे कि किस प्रकार से चुनाव के बाद देश की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गयी है और मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकारें केन्द्रीय सरकार को कोई सहयोग नहीं देना चाहती । केन्द्रीय सरकार को वे बदनाम करना चाहती हैं और यही नहीं, आज जनता का विश्वास प्रदेश की चुनी हुई विधान सभाओं में नहीं, बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रदेशों के मुख्य मंत्री भारत सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं । मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं । नारायण-पुर की जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में उस पर प्रदेश की सरकार ने जो बयान दिया आज उस से ठीक उल्टी बात यहां

माननीय कलराज मिश्र जी बता रहे थे। उस में बिल्कुल असत्य बात को बताया गया है। वहां पुलिस ने जनता पर भारी अत्याचार किया और जब प्रधान मंत्री जी वहां जा कर वहां की स्थिति को देखना चाहती हैं, जो जुल्म हुआ उस की तहकीकात करना चाहती हैं, उन से अपनी हमदर्दी जाहिर करना चाहती हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी को वहां जाना नहीं चाहिए। यह कौन सा संघीय ढांचा है शासन का जिस में एक प्रदेश का मुख्य मंत्री देश के प्रधान मंत्री को अपने स्टेट में जाने से रोके और मना करे। मैं समझता हूं यह एक बात इस बात का सबूत है कि प्रदेश की सरकारें केन्द्रीय सरकार के सामने अड़चन पैदा करना चाहती हैं और संघीय ढांचे को समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी सरकारों को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री उपसभापति : आप ने बहुत समय ले लिया है। कुछ सहयोग कीजिए।

श्री श्यामलाल यादव : जो मुख्य मंत्री संसद सदस्यों के अधिकारों पर हमला करता है उस के लिये क्या कहा जाय। संजय गांधी वहां गये थे और उन्होंने एक बयान दिया उस के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रश्न करते हैं कि उन्हें क्या अधिकार है बयान देने का। मैं समझता हूं कि जहां का मुख्य मंत्री अपने चुने हुए संसद् सदस्यों के बयानों की जांच-पड़ताल करता है, उन पर प्रतिबंध लगता है, मैं समझता हूं कि ऐसे मुख्य मंत्री को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह देश के प्रजातंत्र के लिये खतरा पैदा हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अपने संसद सदस्यों को और प्रधान मंत्री को अपने क्षेत्र में जाने से रोकते हैं और उन की समस्याओं को देखने से रोकते हैं तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है वहां की कानून और व्यवस्था को देखते हुए, देश के जनमत को देखते हुए कि वहां की विधान सभा को भंग करके वहां नये चुनाव कराये जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE DAY

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, with your permission, I have to make an announcement. As the Leader of the Opposition has suggested, and it was the view of the House, that we shall have to sit tomorrow, myself and the Leader of the Opposition sat together to fix the time so far as the business for today is concerned. And both of us have agreed that the first three items mentioned in the Order Paper today, that is, the Appropriation Bill. 1980, the Appropriation (Railways) Bill, 1980 and the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Bill, 1980, will be taken up today. The time will be: the Appropriation Bill, 1980—1½ hours; the Appropriation (Railways) Bill, 1980—1½ hours; the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Bill, 1980—3 hours. And the House will sit late in the evening. We have decided tentatively that we should try to finish before 7 o'clock all the three items of business. The remaining will be taken up tomorrow.

THE APPROPRIATION BILL, 1980—Contd.

SHRI V. B. RAJU (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, the year 1979 has been one of the most disastrous years the country has gone through after independence. There has been galloping inflation. It is as high as 22 per cent at the end of the